भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1747
उत्तर दिनांक 29/07/2026 को दिया गया

उन्नत अनुसंधान के लिए राजा रामन्ना योजना

1747. श्री अनुराग शर्मा

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) देश में उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान, नवाचार और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका सहित राजा रामन्ना योजना की मुख्य विशेषताएं, उद्देश्य और वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस योजना के तहत आवंटित, जारी और उपयोग किए गए धन का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके तहत सहायता प्राप्त अनुसंधान परियोजनाओं, संस्थानों और वैज्ञानिकों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने स्वदेशी अनुसंधान, उभरती प्रौद्योगिकियों और अकादमिक क्षेत्र, अनुसंधान संस्थानों तथा उद्योग के बीच सहयोग को मजबूत करने पर इस योजना के प्रभाव का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार आकांक्षी और पिछड़े क्षेत्रों के युवा अनुसंधानकर्ताओं, स्टार्ट-अपों और संस्थानों की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करके योजना का विस्तार करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्यों के अनुरूप योजना की व्यापक पहुँच, समय पर वित्तीय सहायता और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) परमाणु ऊर्जा विभाग ने पूर्व में संचालित समान योजना का पुनरीक्षण करते हुए अप्रैल 2025 से "डीएई-राजा रामन्ना चेयर" (डीएई-आरआरसी) नामक एक राष्ट्रीय स्तर की योजना प्रारंभ की है। इस योजना का उद्देश्य परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाइयों या किसी राष्ट्रीय प्रयोगशाला या विश्वविद्यालय या संस्थान में अपने-अपने विशिष्ट क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता का अनुसंधान कर चुके सेवानिवृत्ति वैज्ञानिकों, अभियंताओं और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों की विशेषता का उपयोग करना है जो सेवानिवृत्ति के बाद भी डीएई द्वारा निर्धारित विषयों पर अनुसंधान एवं विकास और अध्ययन के इच्छुक हो।

(ख) राजा रामन्ना चेयर योजना अपने वर्तमान स्वरूप में अप्रैल 2025 से प्रचालित है। वर्ष 2025 में देश की विभिन्न इकाइयों, विश्वविद्यालयों और संस्थानों में कार्यरत 22 वैज्ञानिकों और वर्ष 2026 में 6 वैज्ञानिकों को

यह चेयर प्रदान की गई है और इसके लिए 3.78 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित और जारी की गई है। इनमें से 22 वैज्ञानिकों को 2.97 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है और 2.64 करोड़ रुपए की धनराशि का उपयोग हो गया है। शेष 6 वैज्ञानिकों को धनराशि उनके द्वारा अपने मेजबान संस्थानों में शामिल होने और अपेक्षित दस्तावेज जमा करने पर जारी की जाएगी।

(ग) हां। आरआरसी योजना विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्यों के अनुरूप देश में मौलिक विज्ञान अनुसंधान, प्रौद्योगिकीय नवोन्मेष और क्षमता निर्माण के लिए सेवानिवृत्त क्षेत्र विशेषज्ञों द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता का उपयोग करने में बेहद प्रभावी सिद्ध हुई है।

(घ) ऐसा प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(ङ) चेयर प्रदान करने के लिए नामांकन विभिन्न राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और विभाग की इकाइयों से मंगाए जाते हैं। इसके अलावा, योजना स्थायी रूप से डीएई वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाती है। प्रथम वर्ष के लिए वित्तीय सहायता, पुरस्कार विजेताओं के चयन और उनके मेजबान संस्थानों में शामिल होने के आधार पर तत्काल जारी की जाती है। चेयर के दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए, पिछले वर्षों की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा के बाद वित्तीय सहायता जारी की जाती है।

योजना के अंतर्गत चयनित वैज्ञानिकों द्वारा योगदान किए जा रहे प्रमुख अनुसंधान क्षेत्रों में हाइड्रोजन उत्पादन, नाभिकीय में मौलिक और अनुप्रयुक्त अनुसंधान, और उच्च ऊर्जा भौतिकी, खगोल भौतिकी, न्यूट्रिनो भौतिकी, त्वरक विकास और तैनाती, उच्च तीव्रता अतिचालन इलेक्ट्रॉन त्वरक, प्रगत नियंत्रण एल्गोरिदम और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अन्य विशिष्ट क्षेत्र शामिल हैं जो विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्यों के अनुरूप है।

*****